



सब का सपना



राजकीय आईटीआई में वॉक-इन प्रवेश की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर **पेज: 3**

निष्पक्ष व निडर - हिंदी दैनिक समाचार पत्र

'द वन फोर्स ऑफ द फारेस्ट की कामयाबी से खुश हैं **पेज: 8**

वर्ष : 02

अंक : 199

शनिवार 24 अक्टूबर 2026

अमरोहा (उत्तर प्रदेश)

www.sabkasapna.com

पृष्ठ : 08

मूल्य: 2 रुपए

बेंगलुरु मर्डर केस : उम्रकैद काट रही शुभा की दया याचिका कैबिनेट ने की खारिज

बेंगलुरु। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने वर्ष 2003 के चर्चित बेंगलुरु हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रही शुभा शंकरनारायण और उसके साथी डी. अरुण वर्मा की दया याचिकाओं को सर्वसम्मति से खारिज किया गया है। यह मामला 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर बी.वी. गिरीश की निर्मम हत्या से जुड़ा है, जो शुभा के मंगेतर थे। मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में माना गया कि यह हत्या पूरी तरह से सुनियोजित, पूर्व-नियोजित और अत्यंत क्रूर थी। इसलिए मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत दोषियों को किसी भी तरह की राहत या दया नहीं दी जा सकती। डीके मंत्रिमंडल द्वारा खारिज की गई इन याचिकाओं को अब अंतिम फैसले के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोट के पास भेजा जाएगा। राज्य के गृह मंत्री प्रियांक खड्गे ने बताया कि गृह विभाग ने पुलिस और जेल प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट लेने के बाद ही इस विषय को कैबिनेट के समक्ष रखा था। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई 2025 को अपने ऐतिहासिक फैसले में मामले के चारों दोषियों की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा था। हालांकि, अदालत ने उन्हें संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल के समक्ष दया याचिका दायर करने के लिए आठ हफ्ते की मोकलत दी थी। मामले की पृष्ठभूमि के अनुसार, 1 दिसंबर 2003 को इंटेल कंपनी के इंजीनियर गिरीश और लॉ छात्रा शुभा की सगाई हुई थी। परंतु शुभा अपने साथी कानून छात्र अरुण वर्मा से प्यार करती थी और शादी नहीं करना चाहती थी। 3 दिसंबर 2003 की रात शुभा ने गिरीश को छिनर के बहाने बाहर बुलाया, जहां साजिश के तहत गिरीश की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी।

प्रदूषण नियमों की अनदेखी के चलते बीएमडब्ल्यू के हुए 42 बार चालान

नई दिल्ली। दिल्ली की सड़कों पर लगातार बढ़ते प्रदूषण के बीच, जहां नियमों को और कड़ा किया जा रहा है, वहीं कुछ वाहन चालक कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। दिल्ली ट्रेफिक पुलिस के रिकॉर्ड में ऐसी ही एक लक्जरी बीएमडब्ल्यू कार सामने आई है, जिसके नाम पर नियमों के उल्लंघन के 42 चालान दर्ज हैं। चौकाने वाली बात यह है कि इनमें से 24 चालान तो सिर्फ पिछले एक साल के भीतर ही हुए हैं। यह कार दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े नियमों को तोड़ने में सबसे आगे है। 2019 में मॉडल की यह बीएमडब्ल्यू कार साल 2019 से अभी तक बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) के ड्राइविंग करने के लिए लगातार चालान कटवा रही है।

नशामुक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश देने निकले 146 पुलिस राइडर्स

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित लाल परेड ग्राउंड से गुरुवार को एक विशेष राष्ट्रव्यापी बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। फाइट अगेस्ट ड्रम्स (नशे से दूरी है जरूरी) थीम पर आधारित इस रैली में विभिन्न राज्यों के पुलिस बलों और केंद्रीय सुरक्षा बलों के 146 पुलिस राइडर्स शामिल हैं, जो देश में नशामुक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश फैला रहे हैं। इस रैली उद्देश्य केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिश-निर्देशों के तहत युवाओं को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करना और देश में राष्ट्रीय एकता व सामाजिक समरसता का संदेश देना है। यह राइडर्स दल विभिन्न राज्यों से गुजरते हुए लगभग 2,500 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करेगा। इसी के साथ ही यह बाइक रैली 26 अक्टूबर 2026 को गुजरात के एकता नगर (केवडिया) पहुंचेगी। यह दल 31 अक्टूबर 2026 को देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती यानी 'राष्ट्रीय एकता दिवस' के अवसर पर आयोजित होने वाले मुख्य समारोह और परेड में हिस्सा लेगा।

विरोध-प्रदर्शनों पर अन्नामलाई की दो टूक, भाजपा पर भी साधा निशाना

चैन्नई, एंजेंसी। तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के, अन्नामलाई ने कांक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) के विरोध- प्रदर्शनों पर अपने बयानों को लेकर चल रही अटकलों पर स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने साफ किया है कि उनके बयानों को अभिजीत दीपके के नेतृत्व वाले सीजेपी के समर्थन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, हालांकि उन्होंने लोकतंत्र में संघर्ष के अधिकार का समर्थन किया है। गुरुवार को बी द लीडर्स अदोलन के एक कार्यक्रम में बोलते हुए अन्नामलाई ने कई मुद्दों पर बात रखी। उन्होंने कहा, हम कभी भी कांक्रोच जनता पार्टी का समर्थन नहीं करते। उनका एजेंडा अलग है और हमारा अलग है। हालांकि, उन्होंने इसी के साथ यह भी जोड़ा कि लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल को संघर्ष करने का अधिकार है और किसी को भी इससे वंचित नहीं किया जा सकता। दरअसल, दिल्ली में 10 अक्टूबर को सीजेपी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की आलोचना करने के बाद अन्नामलाई पर



बीजेपी ने निशाना साधा था। इस पर पलटवार करते हुए अन्नामलाई ने जोर देकर कहा कि उन्हें देशभक्ति के मामले में किसी से भी उपदेश लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे देश के कई राज्यों में रहने और काम करने का अनुभव है। मैं भारत की एकता और संप्रभुता को समझता हूँ। इसलिए मुझे देशभक्ति पर किसी के उपदेश की जरूरत नहीं है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यदि सीजेपी प्रदर्शनकारियों ने कोई गलत काम किया है, तो अधिकारियों को बदले की भावना रखने के बजाय कानून के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए। अन्नामलाई ने

स्पष्ट किया, हमारा मानना है कि गिरफ्तारियां कानून और उचित प्रक्रिया के अनुसार ही होनी चाहिए। अन्नामलाई ने आगे कहा कि यदि देश की संप्रभुता को कोई खतरा है, तो उसके लिए आईबी और राॅ (आईबी और राॅ) जैसी संस्थाएं हैं, जिनका उपयोग करके दोषियों को जेल में डाला जाना चाहिए, न कि सोशल मीडिया पर मनगढ़ंत बातें फैलाई जानी चाहिए। इसके साथ ही, उन्होंने कहा कि यदि देश को सुनाह आयोग और सुप्रीम कोर्ट जैसी लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता के भरोसे को कमजोर करने की कोशिशों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए अन्नामलाई ने कहा, मोदी एक अच्छे पीएम हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने यह भी जोड़ा कि प्रधानमंत्री का समर्थन करते हुए भी अगर उन्हें कुछ गलत लगता है, तो वे उस पर सवाल उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। उनके इन बयानों ने राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है।

चीन के साथ बढ़ता व्यापार घाटा देश की आर्थिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा

कांग्रेस का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला- मेक इन इंडिया अब इम्पोर्ट फॉम चाइना बना

नई दिल्ली, एंजेंसी। कांग्रेस पार्टी ने चीन के साथ भारत के लगातार बढ़ते व्यापार घाटे को लेकर शुक्रवार को केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि सरकार की नीतियों के कारण 'मेक इन इंडिया' अब 'इम्पोर्ट फॉम चाइना' (चीन से आयात) बनकर रह गया है और रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचता व्यापार घाटा देश की आर्थिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक वीडियो साझा करते हुए दावा किया कि वित्त वर्ष 2025-26 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़कर रिकॉर्ड 112 अरब डॉलर हो गया है, जबकि इससे पिछले वित्त वर्ष में यह 99 अरब डॉलर था। उन्होंने कहा कि चीन से हो रहे भारी-भरकम आयात के कारण देश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) पर बेहद प्रतिकूल असर पड़ रहा है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन के प्रति सोची-समझी रियायतों के चलते सीमा पर हालात चिंताजनक हैं। उन्होंने भारत-तिब्बत सीमा



पुलिस (आईटीबीपी) के महानिदेशक के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें अरुणाचल प्रदेश में पीएलए (चीनी सेना) के साथ हालिया फेंस-ऑफ और सुरक्षा बल के कामकाज की सराहना की गई थी, लेकिन इसके बावजूद सरकार की ओर से इस पर चुप्पी साधी गई है।

जयराम रमेश के अनुसार, स्थानीय लोगों का दावा है कि लद्दाख को तर्ज पर अरुणाचल प्रदेश के कुछ गश्ती बिंदुओं (पेट्रोलिंग प्वाइंट्स) तक पहुंच प्रभावित हुई है। इसके साथ ही बांध और पारिस्थितिकी का खतरा बढ़ा है। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न स्थानों के नाम बदलने के साथ-साथ सीमा के पास 60,000 मेगावाट क्षमता का बांध बनाया जा रहा है, जो भारत की जल और पारिस्थितिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है।

गलवान और पूर्व सैन्य अधिकारियों के बयानों का जिक्र

कांग्रेस नेता ने जून 2020 की गलवान घाटी की झड़प का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री मोदी के उस पुराने बयान पर भी सवाल उठाए, जिसमें देश की सीमा में किसी के घुसने से इनकार किया गया था। इसके अलावा, उन्होंने पूर्व सेना प्रमुखों और शीर्ष सैन्य अधिकारियों के पुराने बयानों और संस्मरणों का हवाला देते हुए केंद्र सरकार की चीन नीति पर पूर्ण पारदर्शिता न बरतने का गंभीर आरोप लगाया है।

अखिलेश ने कहा- कांग्रेस से मिली सीटों पर अंतिम फैसला आजम खां करेंगे

लखनऊ, एंजेंसी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने हाल ही में रामपुर जेल में पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खां से मुलाकात की। इस मुलाकात का मुख्य एजेंडा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस से प्राप्त सीटों की सूची पर गहन मंथन करना था। अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया कि प्रत्याशियों के चयन और सीटों के बंटवारे का अंतिम फैसला आजम खां की राय पर ही आधारित होगा।

एक घंटे से अधिक चली इस महत्वपूर्ण चर्चा ने एक बार फिर मोहम्मद आजम खां के पार्टी के रणनीतिक और नीतिगत फैसलों पर उनके अटूट प्रभाव को उजागर किया है, भले ही वे लंबे समय से सलाखों के पीछे हों। जेल से बाहर निकलने पर अखिलेश का यह बयान कि आजम थे, आजम हैं और आजम ही रहेंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आगामी राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश माना जा रहा है। सियासी गलियारों में इसे सपा मुखिया द्वारा वेस्ट यूपी और



सहेलखंड के सियासी समीकरणों को साधने का एक मास्टस्ट्रोक भी कहा जा रहा है। अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में खुलकर स्वीकार किया कि इंडिया गठबंधन के तहत मिली सीटों की लंबी सूची पर आजम खां के साथ गंभीर रायशुमारी हुई है। उन्होंने कहा कि आजम खां द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण

सुझावों को पूरी तरह से माना जाएगा, उन पर काम किया जाएगा और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई जाएगी। यह पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव ने टिकट बंटवारे पर आजम खां से जेल में सलाह ली हो। 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भी

अखिलेश ने सीतापुर जेल में आजम से मुलाकात कर टिकटों पर अंतिम मुहर लगाई थी। उस सीतापुर मॉडल का परिणाम यह रहा था कि 2022 के चुनाव परिणामों में मुरादाबाद मंडल की 27 विधानसभा सीटों में से 17 पर सपा ने परचम फहराया था। मुरादाबाद मंडल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक अंकड़ों पर नजर डालें तो आज भी वहां सपा की मजबूती के पीछे आजम खां के जनाधारा का सोधा प्रभाव दिखाई देता है। पत्रकारों द्वारा रामपुर सीट से सपा के उम्मीदवार के बारे में पूछे जाने पर, अखिलेश ने अपनी चिर-परिचित मुस्कान के साथ चुटकी लेते हुए कहा, तुम्हें क्यों बताऊं? उनके इस छोटे से जवाब ने सियासी संरक्षकों और गहवा दिया है। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर, आजम खां की यह रणनीतिक सलाह सपा के लिए कितनी फायदेमंद साबित होगी, यह देखना दिलचस्प होगा।

रिजिजू ने की पुष्टि, सऊदी से सुरक्षित लौट रहे उमरा जायरीन

-भारतीय मिशन के मुताबिक यमन तट के पास 14 भारतीय भी हैं सुरक्षित

नई दिल्ली, एंजेंसी। सऊदी अरब और यमन के आसपास बढ़ते तनाव के बीच वहां फंसे भारतीय उमरा जायरीनों की सुरक्षित वतन वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने जानकारी दी है कि संकट में फंसे भारतीय उमरा जायरीन सुरक्षित भारत लौट आए हैं। सरकार की मुस्लेदी से इससे पहले भी 10,000 से अधिक जायरीन स्वदेश लौट चुके हैं, जबकि शेष बचे लोगों की मदद के लिए लगातार प्रयास जारी है। गौरतलब है कि इससे पहले ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एशआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर चिंता जताते हुए बताया था कि 4,000 से अधिक उमरा जायरीन

सऊदी अरब में फंसे हुए हैं। इस मामले पर संज्ञान लेते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पष्ट किया है कि सरकार भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और उनकी समस्याओं के समाधान के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध व सक्रिय है। सहायता के लिए 24 घंटे सक्रिय हैं कंट्रोल रूम भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए रियाद और जेद्दा में भारतीय मिशन चौबीस घंटे मुस्देद हैं। किसी भी आपात स्थिति या सहायता के लिए निम्नलिखित हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। भारतीय दूतावास, रियाद का फोन नंबर +966-554412016, +966-542126784 है, जबकि टेल-फी (सऊदी अरब के भीतर से)= 8002471234 नंबर है। इसके अलावा

व्हाट्सएप (केवल मैसेज) के लिए नंबर +966-536216082 जारी किया गया है। भारतीय वाणिज्य दूतावास, जेद्दा के फोन नंबर +966-12-2614093, +966-556122301 जबकि व्हाट्सएप (केवल मैसेज) के लिए +966-536209704 नंबर जारी किया गया है। यमन तट के पास फंसे नागरिक भी सुरक्षित इस बीच, यमन के तट के पास एक नौका से जुड़े घटनाक्रम में फंसे 14 भारतीय नागरिकों को लेकर भी राहत भरी खबर सामने आई है। भारतीय मिशन ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि रिपोर्टों के अनुसार सभी 14 भारतीय सुरक्षित हैं। सुरक्षा एजेंसियां बरामद सामग्री को आसपास मौजूद हैं। मिशन उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए लगातार संपर्क



में है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले अरब मीडिया में हूती प्रवक्ता याह्या सरी के हवाले से दावा किया गया था कि युकर द्वीप के पास सऊदी बलों ने भारतीयों वाली नौका को निशाना बनाया है, और हूती बल उन्हें बचा रहे

बीजेपी का आरोप, राहुल गांधी कांग्रेस का 'फेल प्रोडक्ट'

राहुल और प्रियंका को फैसलों की जानकारी नहीं

नई दिल्ली, एंजेंसी। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने बताया कि राहुल गांधी के नेतृत्व, विदेश यात्राओं और कांग्रेस के चुनावी प्रदर्शन पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने राहुल गांधी को कांग्रेस का 'फेल प्रोडक्ट' बताकर आरोप लगाया कि पार्टी बार-बार उन्हें आगे करके अपना राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा रही है। हालांकि, ये टिप्पणियां भाजपा नेता के राजनीतिक आरोप हैं। बीजेपी नेता त्रिवेदी ने कहा कि सत्ता से बाहर रहने के कारण कांग्रेस की स्थिति 'जल बिन मछली' जैसी हो चुकी है। राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर निशाना साधकर उन्होंने व्यंग्य किया कि नेता प्रतिपक्ष वियतनाम में हैं और देश की राजनीति से दूर हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज की तुलना राहुल गांधी के राजनीतिक रिकॉर्ड से कर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की

उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं, जबकि राहुल गांधी का रिकॉर्ड समस्याओं से भरा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने कांग्रेस के साथ संवैधानिक संस्थाओं की साख को भी दांव पर प्रेसवार्ता में राहुल गांधी के नेतृत्व, विदेश यात्राओं और कांग्रेस के चुनावी प्रदर्शन पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने राहुल गांधी को कांग्रेस का 'फेल प्रोडक्ट' बताकर आरोप लगाया कि पार्टी बार-बार उन्हें आगे करके अपना राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा रही है। हालांकि, ये टिप्पणियां भाजपा नेता के राजनीतिक आरोप हैं। बीजेपी नेता त्रिवेदी ने कहा कि सत्ता से बाहर रहने के कारण कांग्रेस की स्थिति 'जल बिन मछली' जैसी हो चुकी है। राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर निशाना साधकर उन्होंने व्यंग्य किया कि नेता प्रतिपक्ष वियतनाम में हैं और देश की राजनीति से दूर हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज की तुलना राहुल गांधी के राजनीतिक रिकॉर्ड से कर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की



उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं, जबकि राहुल गांधी का रिकॉर्ड समस्याओं से भरा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने कांग्रेस के साथ संवैधानिक संस्थाओं की साख को भी दांव पर प्रेसवार्ता में राहुल गांधी के नेतृत्व, विदेश यात्राओं और कांग्रेस के चुनावी प्रदर्शन पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने राहुल गांधी को कांग्रेस का 'फेल प्रोडक्ट' बताकर आरोप लगाया कि पार्टी बार-बार उन्हें आगे करके अपना राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा रही है। हालांकि, ये टिप्पणियां भाजपा नेता के राजनीतिक आरोप हैं। बीजेपी नेता त्रिवेदी ने कहा कि सत्ता से बाहर रहने के कारण कांग्रेस की स्थिति 'जल बिन मछली' जैसी हो चुकी है। राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर निशाना साधकर उन्होंने व्यंग्य किया कि नेता प्रतिपक्ष वियतनाम में हैं और देश की राजनीति से दूर हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज की तुलना राहुल गांधी के राजनीतिक रिकॉर्ड से कर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की

संपादकीय

पोषण के भ्रामक दावे

कंपनियों की आक्रामक मार्केटिंग व विज्ञापनों के खेल से भारत में बच्चों के विकास के लिए जरूरी पोषक पदार्थों को बेचने का उपक्रम देश में दशकों से चला आ रहा है। इस प्रचार के खेल में फिल्मी व ग्लैमर की दुनिया की हस्तियां मोटी रकम लेकर शामिल हो जाती हैं। विडंबना यह है कि देश का आम उपभोक्ता देशी-विदेशी खाद्य पदार्थ बेचने वाली कंपनियों के उन दावों पर भरोसा कर लेता है, जिनमें बच्चों के तेज विकास, मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता तथा दिमाग तेज करने के वादे किए जाते रहे हैं। लेकिन वास्तव में माता-पिता को इन दावों के वैज्ञानिक प्रमाण मिलने चाहिए, न कि लुभावने विज्ञापन। शिशुओं के विकास के लिए बनाए गए फार्मूले और कॉम्प्लान से संबंधित दावों को लेकर नेस्ले इंडिया और जाइडस वेलनेस को भारतीय खाद्य संस्का एवं मानक प्राधिकरण यानी एफएसएसएआई द्वारा नोटिस जारी किए गए, जिसने पोषण संबंधी दावों की विश्वसनीयता और सख्त नियामक निगरानी की आवश्यकता पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। नियामक ने कॉम्प्लान से शिशुओं के तीव्र गति से विकास और एकाग्रता, स्मृति तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता से संबंधित लाभ जैसे दावों पर सवाल उठाए हैं। नियामक ने नेस्ले को उसके शिशु आहार के फार्मूले में खास प्रोटीन की पाचन क्षमता और मां के दूध के समान रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक लाभों को प्रमाणित करने के लिए कहा है। निस्पंदेह, उत्पाद खरीदते समय ऐसे दावे माता-पिता के निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। विशेष रूप से जब बच्चे के विकास को लेकर चिंताएं परिवार को बेहतर पोषण के वादों के प्रति संवेदनशील बनाती हैं। इस मामले में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर द्वारा ऑनलाइन प्रचार की भी जांच की गई, जिसमें शिशु आहार फार्मूला उत्पादों की गुणवत्ता की रैंकिंग की गई थी। इसमें दावा किया गया था कि इसके उपयोग से बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता, मस्तिष्क के विकास और पाचन में लाभ मिलता है। आमतौर पर ऐसे प्रचारक मोटी फीस लेकर उपभोक्ताओं को ठेस पहुंचाने का ही काम करते हैं।

निस्संदेह, इस प्रकरण के बाद डिजिटल विज्ञापनों के नियमन को बढ़ाते चुनौती भी सामने आती है। दरअसल, ऐसे भ्रामक व्यावसायिक प्रचार से कभी-कभी वास्तविक लाभ देने वाली सलाह होने का भ्रम भी पैदा हो सकता है। उल्लेखनीय है कि 'शिशु दुग्ध विकल्प अधिनियम' के तहत लगाई गई पारबोदिया विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसका मकसद शिशुओं को माँ का दूध देने की स्वास्थ्यकारी प्रथा को अनुचित व्यावसायिक प्रभावों से होने वाले नुकसान से बचना है। वैसे देखें तो भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा दिए गए ये नोटिस मुनाफे के लिए किए जा रहे किसी गलत कार्य के अंतिम निष्कर्ष नहीं कहे जा सकते हैं। निश्चित रूप से इस प्रकरण में कंपनियों को भी अपना पक्ष रखने का अवसर मिलना ही चाहिए। वहीं दूसरी ओर, उनके बड़-चढ़कर किए जाने वाले दावों की जांच विश्वसनीय सबूतों और नियमों के आधार पर ही की जानी चाहिए। हालाँकि, देश के नियामकों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि बिना तार्किक आधार वाले या गुमराह करने वाले दावों को उत्पाद बनाने वाली कंपनियों द्वारा तुरंत सुधारा जाए। वहीं दूसरी ओर, नियमों का उल्लंघन करने वाले उत्पादकों पर उचित कार्रवाई की जाए। वैसे तो हमारे देश में आमतौर पर खाद्य उत्पादों के लेबल और विज्ञापन ही अक्सर उपभोक्ताओं के लिए जानकारी के मुख्य स्रोत होते हैं। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों व अशिक्षित लोगों में यह समस्या ज्यादा होती है। इसलिए भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण को अपनी जांच-पड़ताल सख्ती से करनी चाहिए। निश्चित रूप से प्रवर्तन एजेंसियों के नतीजे सामने आने पर सार्वजनिक किए जाने चाहिए। साथ ही, भविष्य में यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि निर्माता किसी उत्पाद को बाजार में उतारने से पहले अपने दावों को सच्चाई की कसौटी पर सही साबित करें। निश्चित रूप से पोषण संबंधी मार्केटिंग का मकसद सही जानकारी देना होना चाहिए, न कि लोगों को गुमराह करना।

सूक्ति

जो अप्राप्त वस्तु के लिए चिंता नहीं करता और प्राप्त वस्तु के लिए सम रहता है, वह संतुष्ट कहा जा सकता है।

- महोपनिषद्

जल से शरीर शुद्ध होता है, मन से सत्य शुद्ध होता है, विद्या और तप से भूतात्मा तथा ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होती है।

- मनुस्मृति

आवश्यकता है

आवश्यकता है दैनिक सब का सपना समाचार पत्र को उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर व जिला स्तर पर संवाददाताओं की इच्छुक अभ्यर्थी संपर्क करें या व्हाट्सएप करें।

9456884327/8218179552



गेश कुमार गोयल

ब दलती दुनिया में अप्रासंगिक होता संयुक्त राष्ट्र...

दुनिया के 50 देशों ने वर्ष 1945 में मिलकर 'संयुक्त राष्ट्र अधिकांश पत्र पर हस्ताक्षर कर संयुक्त राष्ट्र' का गठन किया था, जिसके बाद से प्रतिवर्ष 24 अक्तूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। दरअसल द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को अधिक समतार्पणी और न्यायोचित बनाने के लिए एक नए संगठन की स्थापना का विचार अमेरिका था, जो 'पांच राष्ट्र'गंडल सदस्यों तथा आठ यूरोपीय निर्वासित सरकारों द्वारा 12 जून 1941 को लंदन में हस्ताक्षरित 'अंतर-मैत्री उद्घोषणा' में पहली बार सार्वजनिक रूप से स्वीकृत हुआ था। उस उद्घोषणा के अंतर्गत एक स्वतंत्र विश्व के निर्माण हेतु कार्य करने का आह्वान किया गया था, जिसमें एक शांति और सुख के साथ भयमय वातावरण में रह सकें तथा निजीकरण से आर्थिक सहयोग के मार्ग की खोज कर सकें। उसके



ललित गर्ग

स दियों ने अभी पूरी तरह दस्तक भी नहीं दी है कि देश के अनेक शहरों की हवा में प्रदूषण का जहर घुलने लगा है। दिल्ली-एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता का तेजी से बिगड़ना इस बात का संकेत है कि प्रदूषण का संकेत अब केवल सड़ियों की मौसमी समस्या नहीं, बल्कि हमारे पर्यावरणीय प्रबंधन, शहरी विकास और सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने खड़ी एक गंभीर चुनौती बन चुका है। हर साल अक्टूबर-नवंबर में दमघोड़ धुंध, आँखों में जलन, सांस लेने में कठिनाई और अस्पताल में बढ़ती मरीजों की संख्या के साथ यह संकेत सामने आता है। बिड़बंदा यह है कि समस्या के कारणों की पहचान होने और उपायों की जानकारी उपलब्ध होने के बावजूद हम हर वर्ष उसी त्रासदी को दोहराने के लिए विश्व दिखाई देते हैं। समाल यह है कि क्या स्वच्छ हवा में सांस लेना भी अब नागरिकों के लिए एक दुर्लभ सुविधा बनकर रह जाएगा? वायु प्रदूषण किसी एक कारण या किसी एक राज्य की देन नहीं है। वाहनों से निकलने वाला धुआँ, औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण स्थलों से उड़ती धूल, सड़कों पर जमा मिट्टी, कचरा और जैविक पदार्थ जलाना, ताप विद्युत संयंत्रों से होने वाला उत्सर्जन तथा कृषि अवशेषों का दहन

दुनियाँ की नजर इस बात पर टिकी है कि भारत
रुस से किनारा लेती खरीद रहा है, वेनेजुएला से
किनारा लेती खरीद रहा और अमेरिका को दबाव के
आगे भारत अपने फैसले बदलना या नहीं। लेकिन
इस पूरे शोर-शराबे के बीच एक बड़ा सवाल जानबूझकर
नजरअंदाज किया जा रहा है कि इराक से भारत किनारे बाँधी
मात्रा में लेती खरीद रहा है और इस खरीद से अफ्रीका की
हिंटों को कैसे साध रहा है? देखा जाये तो रूस और
वेनेजुएला के तैल पर दुनिया बसक करती रहे, लेकिन भारत
की असली रणनीति समझनी है तो इराक के साथ उसके लेते
कारोबार पर नजर डालनी होगी। यही वह मोर्चा है, जहाँ भारत
अपनी जरूरत, बाजार और कोमत के हिसाब से फैसले
लेकर दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि उसकी ऊर्जा नीति
किसी के दबाव से नहीं, बल्कि देश के हितों से तय होगी।

इराकः भारत को ऊर्जा सुरक्षा का एक बड़ा तन्त्र

देखा जाये तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक है। देश की अर्थव्यवस्था, परिवहन व्यवस्था, उद्योग और आम आदमी के जीवन में पेट्रोलियम की अहम भूमिका है। ऐसे में तेल की कीमतों में मामूली वृद्धि भी भारत के आयात बिल, महंगाई और रुपये पर दबाव डाल सकती है। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में इराक ने भारत को 4.711 करोड़ मेट्रिक टन कच्चा तेल उपलब्ध कराया। यह भारत के कुल तेल आयात के मूल्य का लगभग 19.16 प्रतिशत था। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद इराक भारत का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि इराक भारत के लिए कोई मामूली या वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता नहीं है। वह भारत की ऊर्जा व्यवस्था का एक प्रमुख आधार है। भारतीय तेल कंपनियाँ इराक से निर्यात रूप से तेल खरीदती हैं और इस व्यवहार के माध्यम से दोनों देशों के आर्थिक संबंध भी मजबूत होते हैं।

अक्टूबर 2026 की खरीद-क्यों चर्चा में आया इराक का तेल?

इसक से भारत की खरीद की महत्व हाल के घटनाक्रमों से अलग बड़ गया है। 12 अक्टूबर को रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर में भारत ने इसक से प्रतिदिन लगभग 830 लाख बैरल तेल आयात किया, जबकि अगस्त में यह मात्रा लगभगगति 80 लाख बैरल तेल आयात किया। इसी दौरान भारत का रूस से प्रतिदिन आयात लगभग 14 प्रतिशत घटकर 18 लाख बैरल तेल प्रतिदिन रह गया। यह बदलाव बताता है कि भारत की खरीद किसी एक राजनीतिक समीकरण से तय नहीं होती। जब मध्य-पूर्व का तेल प्रतिस्पर्धी कीमती पर उपलब्ध होता है, तो भारतीय रिफाइनरियां उसकी ओर रुख कर सकती हैं। रूस का तेरे भी भारतीयों बाजार के लिए महत्वपूर्ण बना रहता

बाद 1944 में सोवियत संघ, अमेरिका, चीन तथा ब्रिटेन के प्रतिनिधियों द्वारा वाशिंगटन के डबनरन ओक्स बैठक में कई बैठकों के आयोजन के बाद एक शांतिरक्षक वैश्विक संस्था बनाने की रूपरेखा तैयार की गई, जिसके आधार पर 50 देशों के प्रतिनिधियों के बीच 1945 में बातचीत हुई और 26 जून 1945 को सभी 50 देशों द्वारा चादर पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद यह चार्टर 24 अक्टूबर 1945 से प्रभावी हो गया।

तत्पश्चात से प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को 'संयुक्त राष्ट्र दिवस' मनाया जाने लगता। अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से स्थापित करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ को अद्वितीय शक्तियां प्रदान की गई कि वह अपने सदस्य देशों की सेनाओं को विश्व शांति के लिए कहीं भी तैनात कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद से ही दुनिया के अनेक देश इसमें साथ जुड़ते गए और 50 सदस्यों के साथ शुरू हुए इस वैश्विक संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र की संरचना में सुरक्षा परिषद वाले सबसे शक्तिशाली देश थे अमेरिका, फ्रांस, रूस तथा यूनाइटेड किंगडम, जिनकी द्वितीय विश्वयुद्ध में अहम भूमिका थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य उद्देश्यों में यह प्रेरणा, मानवाधिकारों की रक्षा करना, सभी देशों के बीच मित्रत्व संबंध कायम करना, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को निभाने की प्रक्रिया जुटाना, सामाजिक एवं आर्थिक विकास, निर्यत तथा भूखे लोगों की सहायता करना, उनका जीवन स्तर सुधारना, अंतर्राष्ट्रीय संघों से लड़ना इत्यादि शामिल हैं और इन उद्देश्यों को निभाने के लिए 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा प्रमाणित की गई। हालांकि विध्वन्ना है

जानलेवा होती हवा: सर्दियों से पहले ही प्रदूषण की चुनौती

इसके प्रमुख कारणों में शामिल हैं। सर्दियों में तापमान गिरने, हवा की गति कम होने और वायुमंडलीय परिस्थितियों के कारण प्रदूषक जमीन के निकट जमा हो सकते हैं। इससे प्रदूषण का प्रभाव अधिक गंभीर हो जाता है। इस प्रकार मौसम समस्या को बढ़ाता अवश्य है, लेकिन प्रदूषण पैदा करने वाले मूल कारण मुख्यतः मानवीय गतिविधियों और उनके अपर्याप्त नियमन से जुड़े हैं।

दिल्ली-परासीआर को स्थिति इस संकेत का सबसे स्पष्ट उदाहरण है। दिल्ली के साथ गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और असासपस के अनेक शहर एक-दूसरे से जुड़े वायु क्षेत्र का हिस्सा हैं। इसलिए केवल दिल्ली की सीमाओं के भीतर उपाय करने से समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है। हवा किसी प्रादेशिक सीमा को नहीं मानती, वह प्रदूषण को भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक पहुंचाती है। अतः समाधान भी क्षेत्रीय सहभाग, साझा जवाबदेही और समर्जित कार्ययोजना पर आधारित होना चाहिए। वायु प्रदूषण को सबसे भयावह पथ उसका स्वास्थ्य पर पड़ने वाला प्रभाव है। विशेष रूप से पीएम 2.5 जैसे अत्यंत सूक्ष्म कण प्रदूषकों की गहराई तक पहुंच कर सकते हैं और कुछ परिस्थितियों में रक्तप्रवाह तक प्रवेश कर सकते हैं। इनके लंबे समय तक संपर्क में रहने से हृदय एवं फेफड़ों संबंधी बीमारियों, स्ट्रोक और समग्रपूर्व मृत्यु का जोखिम बढ़ता है। बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं तथा पहले से बीमार लोगों पर इसका प्रभाव विशेष रूप से गंभीर हो सकता है।

यह संकेत केवल सास के मरीजों तक सीमित नहीं है। स्वस्थ दिखाई देने वाले लोगों की कार्यक्षमता, एकाग्रता और जीवन की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। स्कूल जाने वाले बच्चों को खुले मैदान में खेलने से रोकना पड़े, बुजुर्ग सुबह की सैर छोड़ने को विवश हों और श्रमिकों को जहरीली हवा में काम करना पड़े, तो यह

कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के इन 81 वर्षों में खे
वैश्विक स्थिति, सदस्य-धोरे अपनो प्रासंगिकता खोने
है। दरअसल वोटो 81 वर्षों में अंतराष्ट्रीय व्यापार,
अर्थव्यवस्था, हथियार, मीडिया, समाज, मुद्रा तथा
संस्कृति में संवेचित तमाम नीतियों इसके पांच स्थायी
सदस्य देशों ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, रूस तथा फ्रांस
राष्ट्रीय हितों के अनुरूप ही निर्धारित की जाती रही हैं,
जिस कारण ऐसी नीतियों का खामियाजा भारत के
कोलाहा जापान, जर्मनी, आस्ट्रेलिया, इजरायल, दक्षिण
अफ्रीका, ब्राजील, समुद्री अरब, संयुक्त अरब अमीरात
जैसे कई अन्य देशों को भुगतना पड़ा है, जो संयुक्त राष्ट्र
हमसफा की स्थायी सदस्यता के लिए तमाम मारदर्शों
को पूरा करने के बाद भी दशकों में सुरक्षा परिषद के
निर्णायी सदस्य बनने के लिए प्रयासरत हैं। संयुक्त राष्ट्र
की स्थापना के आठ दशकों में विश्व के सामरिक और
आर्थिक समीकरण पूर्ण तरह बदल चुके हैं लेकिन इतना
लंबा समय बीत जाने और तमाम वैश्विक समीकरण हटाने
रूप से बदल जाने के बावजूद वोटो अधिकार वाले
पांचों स्थायी सदस्यों में से कोई भी अपने वोटो
अधिकार और स्थायी सीट को छोड़ने को तैयार नहीं है।
हालांकि स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ने पर संयुक्त राष्ट्र
में आम सहमति है लेकिन चीन को खासकर एशिया के
वोटो अधिकार वाले सदस्यों की संख्या बढ़ाना किसी
भी की वीमट पर स्वीकार नहीं है, जहां स्थायी सदस्यता के
कारणों से संदिग्ध करता है। भारत ने जिस चीन को
मार्गदर्श देते में पहल की थी और सुरक्षा परिषद में उसकी
स्थायी सीट की सिद्धांत के तौर पर लेने से मना कर

केवल पर्यावरण की समस्या नहीं, बल्कि जीवन की परिणाम और नागरिकों के स्वास्थ्य के अधिकांश से जुड़ा प्रश्न है। एयर प्यूरीफायर या मास्क कुछ उपस्थितियों में व्यक्तिगत बचाव में सहायक हो सकते हैं, लेकिन वे व्यक्तिगत हवा की सावजनिक व्यवस्था का विकास नहीं कर सकते। प्रदूषण बढ़ने पर ग्रेडेड रिसॉन्स क्विक्कन प्लान (ग्रेप) लागू करना आवश्यक है। इसके अंतर्गत प्रदूषण की गंभीरता के अनुसार निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध, वाहनों और उद्योगों पर नियंत्रण तथा अन्य आपातकालीन कदम उठाए जाते हैं। लेकिन इन उपायों की प्रभावता केवल आदेश जारी करने से नहीं, बल्कि उनके सफल क्रियान्वयन और निरंतर निगरानी से सुनिश्चित होती है। यदि प्रतियोगिता का उद्देश्य होता रहे, निर्माण स्थलों पर धूल उड़ती रहे और कचरा खुले में जलता रहे, तो सकारात्मक अपेक्षित परिणाम नहीं दे सकती।

सर्वकार को प्रदूषण के चरम पर पहुँचने की प्रतीक्षा करने के बजाय सिम्बर-अक्टूबर से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। प्रदूषण के स्रोतों की पहचान, औद्योगिक इकाइयों की नरीक्षण, सड़कों की नियमित सफाई, निर्माण स्थलों पर धूल निषेध और वाहनों के उत्तरजन की जांच पहले से सुनिश्चित की जानी चाहिए।

सार्वजनिक परिवहन को प्रभावित करना, इलेक्ट्रिक बसें को बढ़ावा देना, स्वच्छ ऊर्जा को विस्तार करना और प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों के विरुद्ध निषेध कार्रवाई करना दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा होना चाहिए।

कृषि क्षेत्र में पराली जलाने की समस्या का समाधान किसानों पर जुर्माना लगाने भर से नहीं होगा। उम्द फसल अक्षयों के प्रबंधन के लिए सस्ती मशीनें, तकनीकी सहायता, आर्थिक प्रोत्साहन और स्थानीय स्तर पर उपयोग की सुविधा उपलब्ध करानी होगी। किसानों को समस्या का भागीदार नहीं, समाधान का सहयोगी बनना होगा।

ये था, आज वही चीन भारत की स्थायी सदस्यता के मामले में रोड़े अटका रहा है। भारत चीन के वोटो पावर के कारण हो सक्ता परिषद का स्थायी सदस्य नहीं बन पा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित किए जाने वाले प्रस्ताव बाध्यकारी प्रकृति के नहीं होते। अश्वथ व बात है कि महासभा में 193 सदस्य देशों द्वारा पारित किए जाने वाले प्रस्ताव भी सुसुखा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों की सहमति पर ही निर्भर करते हैं। इसीलिए अनेक देशों द्वारा इतने संधार किए जाने की मांग बीते कई वर्षों से निरंतर की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र सुसुखा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावदारी की कवालत कर रहे हुए कह चुके हैं कि कि नई ताकतों को केन्द्रीय भूमिका में लाए बिना दुनिया की यह सबसे बड़ी पंचायत स्वयं से की जाने वाली अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पाएगी। दुनिया के कई देश बार-बार पर चरते रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र का इतना अंश पुराना पड़ चुका है और इसकी स्थापना के समय जो परिस्थितियाँ थी, वे अब बहुत पुरानी हो चुकी हैं। इसलिये यदि यह वैश्विक संस्था अपने भीतर सुसुखायामानुसुल्ल सुधार नहीं लाती है तो कालांतर में यह महत्वहीन होती चली जाएगी। रूस-यूक्रेन युद्ध हो या इजरायल-फिलिस्तीन अथवा अमेरिका-ईरान युद्ध, इन संघर्षों में दोनों ही पक्षों के हजारां बेगुनाह लोग मारे रहे हैं, हजारों परिवार उजड़ चुके हैं, लाखों की आबादी आपत्तयान की त्रासदी से जूझ रही है, शहर के शहर मलबे में तब्दील हो रहे हैं लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ इन संधर्षों को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सका है।

प्राचुर्य नियंत्रण की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है। नागरिकों को भी निम्नी वाहनों का अनावश्यक उपयोग कम करने, सार्वजनिक परिवहन अपनाने, कचरा और पतितियां न जलाने तथा ऊर्जा की बचत करने जैसे कदम उठाने होंगे। पर्यावरण संबंधी तथ्यों के उद्घेन की सूचना संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाना और स्थानीय स्तर पर स्वच्छता एवं हरित क्षेत्र बढाने के प्रयासों में भाग लेना भी आवश्यक है। मौजिया, शैक्षणिक संस्थानों और सामाजिक संगठनों के जनजागरूकता अभियान चलाने चाहिए, ताकि स्वच्छ हवा का महत्व केवल प्रदूषण के चरम पर ही याद न आए। साथ ही, वायु गुणवत्ता के आंकड़ों के पारदर्शी ढंग से सार्वजनिक किए जाएं और नागरिकों को प्रदूषण के स्तर के अनुरूप स्वास्थ्य संबंधी सलाह दी जाए।

आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकारें, उद्योग, पेशेवर और नागरिक अपनी-अपनी जिम्मेदारियों से निपटन न हटें। चीन के बीजिंग जैसे शहरों में प्रदूषण घटाने के अनुभव यह बताते हैं कि निरंतर नीतिगत प्रयास, स्वच्छ परिवहन, औद्योगिक नियंत्रण और प्रभावशाली सरकारी से उल्लेखयोग्य सुधार संभव हैं। भारत को भी अपनी परिस्थितियों के अनुरूप ऐसे उपायों को दृढ़ता से लागू करना होगा। हर साल सर्तियों में प्रदूषण से जूझना और फिर मसमल बदनले पर समस्या को भूल जाना किसी भी संवेदनशील समाज की निर्यात नहीं हो सकती। स्वच्छ हवा कोई विलासिता नहीं, जीवन की बुनियादी आवश्यकता है। यदि आज येस करना नहीं उठता एए, तो आने वाली पीढ़ियों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए प्रदूषण का मुकाबला संकेत-संकेत के बाद नहीं, उससे पहले करना होगा। सरकार की सक्रियता, प्रशासन की जवाबदेही और जनता की जागरूकता ही वह त्रिकोण हैं, जिसके आधार पर हम दमयंतू हवा से मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।

दिल्ली में बैठे बैठे मोदी ने इराक़ में कर दिया खेल, भारत के पास अब तेल ही तेल



है, लेकिन खरीद का पैसला कीमत, परिवहन खर्च, उपलब्धता और रिफाइनेरी की जरूरतों के आधार पर होता है। इस रणनीति का मॉड्यूल और उल्लेखनीय उद्धारण सामने आएंगे। इसी महीने की एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने इराक के बसरा टर्मिनल से लगभग 20 लाख बैरल बसरा मीडियम क्रूड की एक खेप खरीदने पर सहमति जताई थी। रिपोर्ट में इस खरीद के लिए दुबई के तेल मूल्य से 32 डॉलर प्रति बैरल कम कीमत का उल्लेख किया गया। यह उद्धारण उस मूल सिद्धांत को सामने लाता है जिस पर भारत की ऊर्जा रणनीति आधारित होनी चाहिए। यानि जहां बेहतर आर्थिक शर्तें मिलें, वहां से तेल खरीदने के विकल्प खुले रखे जाएं।

वीथिक बाजार पर क्या पड़ता है इस्का असर?
देखा जवेल तो तेल बाजार में भारत जैसे बड़े खरीदार का नियोजन केवल उसकी घरेलू उत्पादकता तक सीमित नहीं रहता। भारत प्रतिदिन लाखों बैरल कच्चे तेल का आयात करता है। इसलिए यदि भारतीय कंपनियां रूस के बजाय इराक या दूसरे मध्य-पूर्वी उत्पादकों से अधिक तेल खरीदती हैं, तो अलग-अलग तेल ग्रेड की मांग, व्यापारिक प्रवाह और क्षेत्रीय मूल्य प्रसारणों प्रभावित हो सकती हैं। सितंबर 2026 में मध्य-पूर्व से भारत का कुल तेल आयात बढ़कर लगभग 28 लाख बैरल प्रतिदिन पहुंच गया। यह भारत का कुल तेल

के अनुसार अन्य उत्सवों से तेल खरीदने के विकल्प बनाए रखने चाहिए। इससे किसी एक देश पर अधिक निर्भरता कम होती है। और प्राचिन्यों या आपूर्ति संकट की स्थिति में विकल्प उपलब्ध रहते हैं। तीसरा फायदा है भारत की सीमाईवर्गी की ताकत। जब भारतीय रिफ़ाइनरों कई बाजारों से खरीद संभव है, तो किसी एक आपूर्तिकर्ता की शर्तों को स्वीकार करना उनकी मजबूरी नहीं रह जाता। लेकिन इस हालात को बनाए रखने के लिए समुद्री मार्गों की सुरक्षा, तेल की गुणवत्ता, परिवहन बोमा और भुगतान व्यवस्था का भी ध्यान रखना जरूरी है।

एस्कर अलावा, इराक से प्रतिस्पर्धी शतों पर तेल खरीदना और अंतरराष्ट्रीय दबावों के बावजूद भारत के हितों को संवोधित रखना प्रथममंत्री नरेंद्र मोदी की उर्जा रणनीति का एक बड़ा मास्टरस्ट्रोक है। दुनिया भर की सरकारों तेल की बढ़ती कीमतों और उसके आर्थिक बोझ से जूझ रही हैं, वहीं भारत ने अंतरराष्ट्रीय उथल-पुथल के बीच पेट्रोल-डीजल की घरेलू कीमतों में लाभार्जन स्थिरता बनाए रखकर आज जनता को बड़ी राहत देने की कोशिश की है। रूस हो, इराक हो या कोई दूसरा तेल उत्पादक देश, भारत को जोर से सब बात पर हाँ है। तेल बज्जह में मे मिले, उसको खरीद देश के आर्थिक हितों और उर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखकर की जाए। यही मोदी सरकार की रणनीति की खासियत है। वैश्विक संकट के बीच भारत के लिए बेहतर विकल्प तलाशना और अंतरराष्ट्रीय बजार के बदलाव को संधे आज आदमी की जेब पर खर्च न होने देना। जब दुनिया के कई देश महंगे तेल की चुनौती से जूझ रहे हैं, तब भारत में कीमती को अशुभकृत स्थिर बनाए रखना मोदी सरकार की उर्जा नीति की एक अहम उपलब्धि के रूप में देखा जा सकता है।

हालांकि इराक से तेल खरीदने में जीखिम भी हैं। खाड़ी क्षेत्र में संघर्ष, हेमूज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा और आपूर्ति में संभावित बाधाएं भारत के लिए गंभीर चुनौती बन सकती हैं। इसलिए सस्ता तेल तभी वास्तविक रणनीतिक लाभ है, जब उसकी आपूर्ति भरोसेमंद और आर्थिक रूप से व्यवहार्य भी हो।

बहराला, दुनिया भारत की रूस से तेल खरीद पर नजर रखे जा वेनेजुएला से संभावित खरीद पर बहस करे, भारत की ०८०० नीती का भूयंत्रण व्यवहार तस्वीर के आधार पर होना चाहिए। इराक से 4,711 करोड़ टन बाँकि तेज आपूर्ति और सितंबर 2026 में वहां से आयात में अर्द्ध तेज बढ़ोतरी और दिखता है कि मध्य-पूर्व भारत की ऊर्जा सुरक्षा में कितनी अहम भूमिका निभाता है। यदि मोदी सरकार और भारतीय तेल कंपनियां प्रतिस्पर्धी कीमतों, सुस्थिति अपूर्ति और दीर्घकालिक कटौती सुरक्षा को एक साथ साध पाती हैं, तो यह व्यावहारिक कुटीनी की बड़ी समलता होगी।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कौराल न्याय पंचायत में मत्स्य पालन एवं बहुउद्देशीय समिति के गठन हेतु दिनांक 25.10.2026 को ग्राम चमरौवा न्याय पंचायत कौराल विकास खण्ड अमरोहा में प्रातः 11:00 बजे पंचायत घर में बैठक आयोजित की जायेगी।

स्वच्छ मंडी-शुभ मंडी अभियान के तहत किरतपुर और नजीबाबाद मंडी का औचक निरीक्षण

सफाई, पेयजल और जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश, सीसीटीवी फुटेज से अभिलेखों का मिलान कराने पर जोर



बिजनौर (सब का सपना):— जिले की मंडियों को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे स्वच्छ मंडी-शुभ मंडी अभियान के तहत अधिकारियों द्वारा निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मुरादाबाद मंडल के उपनिदेशक शिवकुमार राघव ने दूसरे दिन किरतपुर और नजीबाबाद मंडी का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सफाई व्यवस्था, गोदामों, दुकानों, क्षतिग्रस्त दीवारों और जल निकासी की स्थिति का बारीकी से निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-

निर्देश दिए। उपनिदेशक ने मंडी परिसर में जमा कूड़ा-कचरा और मलबा तत्काल हटाने, रंगाई-पुताई कराने, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा दुकानों के पीछे सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मंडियों में स्वच्छता और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए सभी आवश्यक कार्य निधरित समय-सीमा के भीतर पूरे किए जाएं। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मंडी के प्रवेश द्वार पर जारी होने वाली प्रवेश पर्चियों और कलें में से संबंधित अभिलेखों का सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से मिलान करने तथा चेकपोस्ट रजिस्टर



की जांच करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने व्यवस्थाओं में पारदर्शिता बनाए रखने और निरीक्षण के दौरान सामने आने वाली कमियों को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने पर जोर दिया। नजीबाबाद मंडी में व्यापारी हाशिम अहमद, डॉ. इदरीस अंसारी और अयाज आलम ने मंडी की व्यवस्थाओं में सुधार के लिए की जा रही पहल की सराहना करते हुए उपनिदेशक शिवकुमार राघव को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस दौरान व्यापारियों ने मंडी से जुड़ी विभिन्न समस्याओं से भी उन्हें अवगत कराया। वहीं, गल्ला मंडी के व्यापारी संजय राजपूत और सुनील

आर्य ने पेयजल की समस्या उठाई। इस पर उपनिदेशक ने संबंधित अधिकारियों को समस्या का जल्द समाधान कराने के निर्देश दिए, ताकि मंडी में आने वाले व्यापारियों और अन्य लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। उधर, बरेली से पहुंचे उपनिदेशक विद्युत यांत्रिक आलोक निधि गोयल ने भी मंडी का निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए 20 बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार की। अभियान के तहत अधिकारियों ने मंडियों में साफ-सफाई, मूलभूत सुविधाओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने पर विशेष जोर दिया।

आवारा कुत्ते के हमले में 15 वर्षीय छात्र गंभीर रूप से घायल

कुत्ते ने शरीर पर कई जगह काटकर किया लहलुहान, सीएचसी में भर्ती

नगीना/बिजनौर सब का सपना):— नगर के आजाद कॉलोनी लाइन पार मोहल्ले में शुक्रवार दोपहर आवारा कुत्ते ने घर के बाहर खड़े 15 वर्षीय छात्र पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। कुत्ते ने छात्र के शरीर पर कई जगह काटकर उसे लहलुहान कर दिया। छात्र की चीख-पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे परिजनों और आसपास के लोगों ने किसी तरह उसे कुत्ते के चंगुल से बचाया।

घायल छात्र को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, आजाद कॉलोनी लाइन पार निवासी नगर पालिका कर्मचारी विनोद ठाकुर का 15 वर्षीय पुत्र रितांत कुमार ठाकुर शुक्रवार दोपहर अपने घर के बाहर सड़क पर खड़ा था। इसी दौरान मोहल्ले में घूम रहे एक आवारा कुत्ते

ने अचानक उस पर हमला कर दिया। कुत्ते ने छात्र को कई जगह काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसकी आवाज सुनकर परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तथा काफी मशक्कत के बाद उसे कुत्ते से बचाया। इसके बाद परिजन घायल छात्र को तत्काल सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां उसे भर्ती कर उपचार शुरू किया गया। घायल छात्र के पिता विनोद ठाकुर ने बताया कि

उक्त आवारा कुत्ता पहले भी कॉलोनी के दर्जनों लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर चुका है। इसके बावजूद कुत्ते के आतंक से लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। घटना के बाद से मोहल्ले के लोगों में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने संबंधित अधिकारियों से आवारा कुत्ते को पकड़वाने और लोगों को उसके आतंक से निजात दिलाने की मांग की है।

शिक्षक एमएलसी पद के लिए हुआ मतदान रहा शांतिपूर्ण

नगीना/बिजनौर (सब का सपना):— बरेली मुरादाबाद खंड शिक्षक एमएलसी पद के लिए हुआ मतदान शांतिपूर्ण हुआ, मतदान स्थलों पर भारी पुलिस तैनात रहा। चुनाव में 17 प्रत्याशी मैदान में है लेकिन पांच प्रत्याशियों की हि बस्ते रखे मिले। कुल 694 में से 60% 414 ही मत पढ़ सके। 23 अक्टूबर को हुए शिक्षक एमएलसी पद के चुनाव के लिए हिंदू इंटर कॉलेज ने मतदान केंद्र बनाए गए थे, इन मतदान केंद्रों पर विकासखंड कोतवाली क्षेत्र के कुल 689 मतदाता है जिन्हें 369 शिक्षक और 320 शिक्षिकाएं मतदाता है, शुक्रवार की सुबह 8 बजे मतदान शुरू हुआ। स्टेशन रोड स्थित गांधी मूर्ति तिहाड़े पर शिक्षक एमएलसी पद के प्रत्याशी भाजपा प्रत्याशी सरदार हरि सिंह



दिल्लो, सपा के हाजी दानिश अख्तर, उ प्र माध्यमिक शिक्षक संघ के डॉक्टर सुनील गिरी, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के विमलेंद्र शर्मा, एवं डॉक्टर राजेंद्र कुमार गंगवार समेत पांच प्रत्याशियों के ही बस्ते रखे दिखाई पड़े अन्य किसी प्रत्याशी का कोई वास्ता या कार्यकर्ता नजर नहीं आया। मतदान सुबह से ही धीमी गति से चला। भाजपा

प्रत्याशी हरि सिंह दिल्लों अपने काफिले के साथ नगीना पहुंचे और भाजपाइयों अनूप वाल्मीकि, पूर्व विधायक सतीश कुमार, सौरभ मित्तल, अरविंद गहलोत, कृष्ण बलदेव, पूर्व सांसद डॉ यशवंत सिंह, चुनाव प्रभारी सतपाल सिंह, दिग्विजय सिंह चौधरी, डॉक्टर भूपेश कुमार, सोहन सैनी, पंडित सचिन शर्मा, प्रमोद चौहान सरदार हरमीत

सिंह, प्रहलाद कुशवाहा, मनोज टंडन सभी कार्यकर्ताओं से मतदान के संबंध में जानकारी की और मतदान स्थल भी पहुंचे जहां अपने मतदान एजेंट डॉक्टर संदीप शर्मा से संपर्क कर जानकारी दी। सपा के हाजी डेनिस अख्तर के बेस्ट की कमान शोएब इकबाल संकज अग्रवाल राधा सैनी डॉ योगेंद्र धर्मवीर सिंह शमशाद राशिद महीगीर के हाथों में रही। 694 में से कुल 414 मत पड़े। मतदान शांति पूर्वक संपन्न करने के लिए थाना प्रभारी धर्मेन्द्र कुमार भारी पुलिस बल के साथ मतदान स्थल पर मौजूद रहे, तथा एसडीएम प्रिंस कुमार, वे सीओ राजेश कुमार सोलंकी, ने मध्य स्थलों का और सुरक्षा व्यवस्था का कड़े मर्तबा जय जालियां, और तैनात पुलिस कर्मियों को किसी तरह की गड़बड़ी न होने एए हिदायत देते रहे।

नूरपुर में एमएलसी चुनाव के लिए मतदान शुरू, सपा पदाधिकारियों ने संभाली जिम्मेदारी

बृथ संख्या 62 पर सुबह आठ बजे से शुरू हुई वोटिंग, सपा प्रत्याशी हाजी दानिश अख्तर के एजेंटों ने संभाला मोर्चा



नूरपुर/बिजनौर (सब का सपना):— बरेली-मुरादाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी चुनाव के तहत नूरपुर स्थित खंड विकास कार्यालय के बृथ संख्या 62 पर शुक्रवार सुबह आठ बजे मतदान शुरू हुआ। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी दानिश अख्तर के बृथ एजेंट कुलदीप सैनी और अरुण कुमार ने मतदान प्रक्रिया की शुरूआत कराई। मतदान केंद्र पर मतदाताओं की सुविधा के लिए सपा

कार्यकर्ता मतदाता सूची में नाम और क्रमांक की जानकारी देते नजर आए। इस दौरान समाजवादी पार्टी के जिला सचिव देवेन्द्र यादव, जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद दिलदार तथा लोहिया वाहिनी के जिला मीडिया प्रभारी सज्जा उद्दीन अल्वी ने भी मतदान संबंधी कार्यों में सहयोग किया। कार्यकर्ताओं ने मतदाताओं को मतदाता सूची में उनका नाम और क्रमांक बताकर आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई। मतदान केंद्र पर



नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक राम अवतार सिंह सैनी, समाजवादी आंदोलन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अकबर नबी इदरीसी, सपा के जिला महासचिव धनंजय यादव, समाजवादी आंदोलन पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष कल्याण दत्त शर्मा, जिला पंचायत सदस्य वाई संख्या पांच नूरपुर ब्लॉक के प्रत्याशी सलीम अहमद, सपा जिला सचिव मुकर्रम अल्वी, समाजवादी आंदोलन पार्टी

के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मोहम्मद रफी मिकरानी, नूरपुर ब्लॉक के वाई संख्या चार से जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी मास्टर कमल यादव, अल्पसंख्यक जिला उपाध्यक्ष सईद अहमद अंसारी, समाजवादी आंदोलन पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मुफ्ती इफ्तिखार कासमी, नगीना लोकसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी धर्मवीर सिंह दिवाकर तथा युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. वसोम सिद्दीकी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

फतेहपुर में 17,596 मतदाताओं में से 8,306 ने किया मतदान, कुल मतदान 47.20 प्रतिशत

फतेहपुर (सब का सपना):— जिले में विभिन्न मतदेय स्थलों पर हुए मतदान में कुल 17,596 मतदाताओं में से 8,306 मतदाताओं ने अपने मतदाधिकार का प्रयोग किया। इनमें 6,067 पुरुष और 2,239 महिलाएं शामिल हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कुल मतदान प्रतिशत 47.20 रहा। अमौली स्थित कार्यालय क्षेत्र पंचायत के दो मतदेय स्थलों पर क्रमशः 53.88 और 55.22 प्रतिशत मतदान दर्ज किया

उपचयन क्षेत्र के मतदाताओं के मतदान की जानकारी-2026									
कुल मतदाता-17,596 मतदान-8,306 मतदान प्रतिशत-47.20, अक्टूबर 2026									
क्र.सं.	मतदाताओं की संख्या	मतदान की संख्या	मतदान प्रतिशत	मतदाताओं की संख्या	मतदान की संख्या	मतदान प्रतिशत	मतदाताओं की संख्या	मतदान की संख्या	मतदान प्रतिशत
1	100	45	45.00	200	90	45.00	300	135	45.00
2	200	90	45.00	300	135	45.00	400	180	45.00
3	300	135	45.00	400	180	45.00	500	225	45.00
4	400	180	45.00	500	225	45.00	600	270	45.00
5	500	225	45.00	600	270	45.00	700	315	45.00
6	600	270	45.00	700	315	45.00	800	360	45.00
7	700	315	45.00	800	360	45.00	900	405	45.00
8	800	360	45.00	900	405	45.00	1000	450	45.00
9	900	405	45.00	1000	450	45.00	1100	495	45.00
10	1000	450	45.00	1100	495	45.00	1200	540	45.00
11	1100	495	45.00	1200	540	45.00	1300	585	45.00
12	1200	540	45.00	1300	585	45.00	1400	630	45.00
13	1300	585	45.00	1400	630	45.00	1500	675	45.00
14	1400	630	45.00	1500	675	45.00	1600	720	45.00
15	1500	675	45.00	1600	720	45.00	1700	765	45.00
16	1600	720	45.00	1700	765	45.00	1800	810	45.00
17	1700	765	45.00	1800	810	45.00	1900	855	45.00
18	1800	810	45.00	1900	855	45.00	2000	900	45.00
19	1900	855	45.00	2000	900	45.00	2100	945	45.00
20	2000	900	45.00	2100	945	45.00	2200	990	45.00
21	2100	945	45.00	2200	990	45.00	2300	1035	45.00
22	2200	990	45.00	2300	1035	45.00	2400	1080	45.00
23	2300	1035	45.00	2400	1080	45.00	2500	1125	45.00
24	2400	1080	45.00	2500	1125	45.00	2600	1170	45.00
25	2500	1125	45.00	2600	1170	45.00	2700	1215	45.00
26	2600	1170	45.00	2700	1215	45.00	2800	1260	45.00
27	2700	1215	45.00	2800	1260	45.00	2900	1305	45.00
28	2800	1260	45.00	2900	1305	45.00	3000	1350	45.00
29	2900	1305	45.00	3000	1350	45.00	3100	1395	45.00
30	3000	1350	45.00	3100	1395	45.00	3200	1440	45.00
31	3100	1395	45.00	3200	1440	45.00	3300	1485	45.00
32	3200	1440	45.00	3300	1485	45.00	3400	1530	45.00
33	3300	1485	45.00	3400	1530	45.00	3500	1575	45.00
34	3400	1530	45.00	3500	1575	45.00	3600	1620	45.00
35	3500	1575	45.00	3600	1620	45.00	3700	1665	45.00
36	3600	1620	45.00	3700	1665	45.00	3800	1710	45.00
37	3700	1665	45.00	3800	1710	45.00	3900	1755	45.00
38	3800	1710	45.00	3900	1755	45.00	4000	1800	45.00
39	3900	1755	45.00	4000	1800	45.00	4100	1845	45.00
40	4000	1800	45.00	4100	1845	45.00	4200	1890	45.00
41	4100	1845	45.00	4200	1890	45.00	4300	1935	45.00
42	4200	1890	45.00	4300	1935	45.00	4400	1980	45.00
43	4300	1935	45.00	4400	1980	45.00	4500	2025	45.00
44	4400	1980	45.00	4500	2025	45.00	4600	2070	45.00
45	4500	2025	45.00	4600	2070	45.00	4700	2115	45.00
46	4600	2070	45.00	4700	2115	45.00	4800	2160	45.00
47	4700	2115	45.00	4800	2160	45.00	4900	2205	45.00
48	4800	2160	45.00	4900	2205	45.00	5000	2250	45.00
49	4900	2205	45.00	5000	2250	45.00	5100	2295	45.00
50	5000	2250	45.00	5100	2295	45.00	5200	2340	45.00
51	5100	2295	45.00	5200	2340	45.00	5300	2385	45.00
52	5200	2340	45.00	5300	2385	45.00	5400	2430	45.00
53	5300	2385	45.00	5400	2430	45.00	5500	2475	45.00
54	5400	2430	45.00	5500	2475	45.00	5600	2520	45.00
55	5500	2475	45.00	5600	2520	45.00	5700	2565	45.00
56	5600	2520	45.00	5700	2565	45.00	5800	2610	45.00
57	5700	2565	45.00	5800	2610	45.00	5900	2655	45.00
58	5800	2610	45.00	5900	2655	45.00	6000	2700	45.00
59	5900	2655	45.00	6000	2700	45.00	6100	2745	45.00
60	6000	2700	45.00	6100	2745	45.00	6200	2790	45.00
61	6100	2745	45.00	6200	2790	45.00	6300	2835	45.00
62	6200	2790	45.00	6300	2835	45.00	6400	2880	45.00
63	6300	2835	45.00	6400	2880	45.00	6500	2925	45.00
64	6400	2880	45.00	6500	2925	45.00	6600	2970	45.00
65	6500	2925	45.00	6600	2970	45.00	6700	3015	45.00
66	6600	2970	45.00	6700	3015	45.00	6800	3060	45.00
67	6700	3015	45.00	6800	3060	45.00	6900	3105	45.00
68	6800	3060	45.00	6900	3105	45.00	7000	3150	45.00
69	6900	3105	45.00	7000	3150	45.00	7100	3195	45.00
70	7000	3150	45.00	7100	3195	45.00	7200	3240	45.00
71	7100	3195	45.00	7200	3240	45.00	7300	3285	45.00
72	7200	3240	45.00	7300	3285	45.00	7400	3330	45.00
73	7300	3285	45.00	7400	3330	45.00	7500	3375	45.00
74	7400	3330	45.00	7500	3375	45.00	7600	3420	45.00
75	7500	3375	45.00	7600	3420	45.00	7700	3465	45.00
76	7600	3420	45.00	7700	3465	45.00	7800	3510	45.00
77	7700	3465	45.00	7800	3510	45.00	7900	3555	45.00
78	7800	3510	45.00	7900	3555	45.00	8000	3600	45.00
79	7900	3555	45.00	8000	3600	45.00	8100	3645	45.00
80	8000	3600	45.00	8100	3645	45.00	8200	3690	45.00
81	8100	3645	45.00	8200	3690	45.00	8300	3735	45.00
82	8200	3690	45.00	8300	3735	45.00	84		

टाईम पास

16. निरंकुश, मुंहजोर
-4

बं	दा	न	बा	ज	आ	स	मा	न
न	दी	र	ल	बा	दा	र	जा	न
ख	ज	म	ज	म	ब	नी	क	न

17. किनारा, टट

जी	म	ना	ह	ठ	ता	क	त
----	---	----	---	---	----	---	---

18. कामधेनु,
सुगंध-3

ब	बा	ज	जे	ल	पे	ता	न
न	ग	र	से	ठ	फ	का	र
नी	न	स	फ	ता	ते	म	न

20. नुकसानदेह-5

सु	ब	ह	दा	य	बा	री	क
----	---	---	----	---	----	----	---

21. दुनिया, जग-3

क	श	प्र	न	का	र	क
---	---	-----	---	----	---	---

22. कलामुनी-4

ता	प	प	र	दा	म	क	ण
----	---	---	---	----	---	---	---

23. चयन-3

ल	ख	य	र	च	ना	का	र
---	---	---	---	---	----	----	---

